आज का मौसम

भोपाल	↑ 24.9°	↓ 22.5°
इंदौर	↑ 25.9°	↓ 22.2°
ग्वालियर	↑ 27.2°	↓ 25.2°
जबलपुर	↑ 27.7°	↓ 23.0°

सूर्योदय- 5.49 सूर्यास्त-7.04

दैनिक

नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

सिंधु अंतिम 16 में हांगकांग की... 8

वर्ष- 75 (भोपाल: वर्ष 36 अंक 242, पृष्ठ 8) गुरुवार 29 जुलाई , 2021 राजधानी संस्करण. कीमत: रु. 3:00 www.naiduniaonline.com

खास-खबर

बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर मिलेगा पैसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी कैबिनेट ने बैंक बंद होने की स्थिति में खाताधारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपये तक की अपनी राशि हासिल करने की सुरक्षा देने को लेकर डीआईसीजीसी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन के साथ जमा बीमा का दायरा बढ़ जाएगा और इसके अंतर्गत 98.3 प्रतिशत बैंक खाताधारक पूरी तरह संरक्षित हो जाएंगे। सीतारमण ने कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद (शेष पेज 2 पर)

राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर

नई दिल्ली (एजेंसी)। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी जगह आईटीबीपी के डीजी एसएस देशवाल को बीएसएफ डीजी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। सेवानिवृत्ति से महज तीन दिन पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।

लोकसभा में जमकर हंगामा

कांग्रेस के पर्चा फाड़ सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव लाएगी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान हंगामा करने और पर्चे फेंकने वाले 10 विपक्षी सांसदों के खिलाफ सरकार की ओर से निलंबन प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर के समक्ष कांग्रेस नेता टीएन प्रतापन, हिबी एडन, गुरजीत सिंह आहूजा, बिट्टी, मणिकल टैगोर, दीपक बैज, एएम आरिफ और ज्योतिमणि समेत 10 लोगों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

बुधवार को लोकसभा में एक बार फिर से पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। यही नहीं इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने पर्चे फाड़े प्लेकार्ड्स फेंक दिए। इसे लेकर सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। विपक्षी दलों की ओर से लगातार हंगामे के चलते सदन को तीन बार स्थगित करना पड़ा। हालांकि तमाम व्यवधानों के बाद भी किसी तरह से प्रश्न काल पूरा हो गया। इस मॉनसून सेशन में यह पहला मौका था, जब प्रश्न काल पूरा हुआ। कांग्रेस और टीएमसी के सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान प्रश्न काल समाप्त होते ही स्पीकर ओम बिरला सदन से चले गए और उनकी जगह पर राजेंद्र अग्रवाल बैठे। इसी दौरान कांग्रेस सांसदों ने दिन की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेजों को फाड़ना शुरू कर दिया और कुछ पेज आसन की ओर भी फेंके। यही नहीं एक प्लेकार्ड का टुकड़ा स्पीकर के आसन के पास प्रेस गैलरी में भी आकर गिरा। हालांकि इस दौरान भी राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही को जारी रखा। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस सांसदों के व्यवहार पर हमला बोला है। यही नहीं विपक्षी दल के हंगामे को लेकर बीजेपी ने कहा कि कोरोना संकट पर कोई चर्चा न होने देना राष्ट्रविरोधी है। यही नहीं बीजेपी की ओर से विपक्षी दलों की एकता को लेकर भी निशाना साधा गया। भाजपा ने कहा कि पहले भी ये सभी दल पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। इसकी वजह अपने पारिवारिक हितों को साधना है। राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में पेगासस जासूसी को लेकर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र विरोधी काम था। इस पर जवाब देते हुए भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोरोना संकट पर चर्चा न होने देना राष्ट्रविरोधी है। कोरोना संकट ने बुरी तरह से देश को प्रभावित किया था और इस पर चर्चा होनी चाहिए।

पेगासस मामला 'मनगढ़ंत' मुद्दा, कोरोना पर संसद में चर्चा न होने देना 'राष्ट्रविरोधी': बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बुधवार को कथित पेगासस जासूसी मामले को 'मनगढ़ंत' मुद्दा करार दिया और इसे लेकर संसद में हंगामा करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोविड-19 मुद्दे पर संसद में चर्चा ना होने देना 'राष्ट्रविरोधी' कृत्य है। बीजेपी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है और तीसरी लहर से निपटना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, कांग्रेस द्वारा कथित पेगासस जासूसी मामले को सबसे बड़ा मुद्दा बताना विपक्ष के ' दिवालियेपन ' का परिचायक है। उन्होंने कहा कि संसद में कोविड-19 (मुद्दे)पर चर्चा ना करना राष्ट्रविरोधी है। पूरे विश्व में जिस महामारी को लेकर सैकड़ों लोगों की जान चली गई,जिस महामारी को लेकर हर देश में आज परेशानी है, उस विषय पर अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चर्चा न करें, बहस न करें तो वह देश के खिलाफ है। पात्रा ने कहा कि जो भी इस विषय पर होने वाली चर्चा को रोकता है तो वह कहीं ना कहीं देश के ऊपर आघात करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए? हर जिले में ऑक्सीजन संयंत्र लगे इसकी चिंता की जानी चाहिए कि नहीं?लेकिन चर्चा नहीं होने दी जा रही है...कागज फाड़ा जा रहा है...यह धोखा है...देश के साथ और देश की जनता के साथ। उन्होंने कहा कि पेगासस मुद्दा 'मनगढ़ंत ' है और यह कोई विषय ही नहीं है जिस पर इतना हंगामा मचाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके विपक्ष देश को बरगला नहीं सकता है।'' ज्ञात हो कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल पेगासस जासूसी विवाद पर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहे हैं। हंगामे के कारण मानसून सत्र में अब तक कोई विशेष कामकाज नहीं हो सका है।

सरकारी जांच एजेंसियों को फ्री हैंड

भ्रष्ट अफसरों की अब सीधे कर सकेंगी जांच

भोपाल (काप्र)।

लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को भ्रष्ट अफसर या कर्मचारी के खिलाफ जांच के लिए संबंधित विभाग से इजाजत नहीं लेनी होगी।

सरकार ने 7 महीने पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में बदलाव कर जांच एजेसिंयों की ताकत कमजोर कर दी थी। इसे लेकर लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता ने सरकार से पूछा था कि एक्ट में बदलाव से पहले अनुमति क्यों नहीं ली गई? लोकायुक्त ने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार और प्रमुख सचिव (कार्मिक) दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नोटिस दिया था। अफसरों को 29 जुलाई को जवाब पेश करना था, लेकिन इसके एक दिन पहले ही राज्य शासन ने एक्ट में जोड़ी गई धारा (17ए) हटा दी है। इस धारा के तहत बने उस नियम को सरकार हटा रही है, जिसमें लोकायुक्त-ईओडब्ल्यू को जांच के लिए विभाग की अनुमति लेनी पड़ती थी। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

राज्य सरकार ने 26 दिसंबर 2020 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-17 में 17-ए जोड़ी थी। इसके तहत लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू समेत अन्य जांच एजेंसियों को सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जांच, पूछताछ से पहले विभाग से अनुमति लेने का प्रावधान जोड़ा गया था। इससे पहले, शिकायत के आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ये एजेंसियां सीधी जांच करती थी, लेकिन प्रदेश सरकार के नए आदेश के तहत उनसे ये अधिकार छीन लिए थे। इसके तहत ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जैसी एजेंसियां जांच के लिए शिकायतों को भ्रष्ट अधिकारियों के विभाग के पास भेज रही थीं। इसके बाद उसका विभाग ही तय करता कि मामले की जांच कराई जानी चाहिए (शेष पेज 2 पर)

भाजपा ही दिलवाएगी ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण: भूपेंद्र सिंह

भोपाल (काप्र)।

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य की सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए अदालत सहित किसी भी मंच पर सभी जरूरी प्रयास किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस संकल्प और उसे पूरा करने की प्रभावी कोशिशों के चलते इस आरक्षण के लिए किसी आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। श्री सिंह बुधवार को भोपाल में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में चौथी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए पुरजोर प्रयास किये हैं। जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार इस मामले में केवल टालमटोली करती रही, जिसके चलते उस समय हाई कोर्ट में इस वर्ग की आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से नहीं रखा गया।

श्री सिंह ने कहा कि भाजपा शुरू से ही ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए प्रयासरत है। इसके चलते ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। अब मध्य प्रदेश की सरकार विधानसभा की एक स्टैंडिंग कमेटी बना रही है। यह समिति ओबीसी आरक्षण के संबंध में पूरा अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार (शेष पेज 2 पर)

सोनिया से मिलीं ममता, पेगासस सहित कई मुद्दों पर की चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पांच दिवसीय दिल्ली दौरे के तीसरे दिन आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। ममता ने ये मुलाकात ऐसे समय में की है जब विपक्ष की एकजुटता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पेगासस, कृषि कानू और महंगाई के मुद्दे पर संसद ठप है।

सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात सकारात्मक रही। विपक्षी एकता और पेगासस पर चर्चा हुई। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ममता ने पेगासस को लेकर कहा कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। संसद में सरकार जवाब दे। ममता ने सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि विपक्षी दलों की एकजुटता हो। कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दलों पर विश्वास है। ममता ने आगे कहा कि अगर सभी क्षेत्रीय दल इकट्ठा हो जाएं तो एक दल पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता और चेहरे को लेकर कहा कि मैं राजनीतिक ज्योतिषी नहीं हूं, स्थिति पर निर्भर (शेष पेज 2 पर)

लोकतंत्र की आत्मा पर चोट की गई, पेगासस पर चर्चा हो : राहुल

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह पर पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके लोकतंत्र की आत्मा पर चोट करने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि सरकार ने पेगासस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है।

उन्होंने कहा कि हमारी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ यह सवाल है कि क्या भारत सरकार ने पेगासस को खरीदा?...हां या ना। क्या सरकार ने अपने ही लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया ? हां या ना। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ पेगासस रूपी हथियार का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा (शेष पेज 2 पर)

एमपी बोर्ड की 12वीं का परीक्षा परिणाम आज

भोपाल (काप्र)। मध्य प्रदेश बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कल यानी 29 जुलाई को कक्षा 12वीं का परिणाम जारी करने वाला है। परिणाम की घोषणा कल दोपहर 12 बजे की जाएगी। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 12वीं का नतीजा अपनी आधिकारिक वेसबाइट mpresultsÐnicÐin पर जारी करेगा। एमपीबीएसई के आंकड़ों के अनुसार करीब 7.5 लाख छात्रों को एमपी बोर्ड 12वीं के परिणाम का इंतजार है। बता दें कि कोविड-19 के कारण मध्यद्व प्रदेश बोर्ड ने भी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। लिहाजा, 12वीं का रिजल्टा, इंटरनल असेसमेंट पॉलिसी के आधार पर तैयार किया गया है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह अपना रोल नंबर तैयार रखें। हालांकि छात्र अपना परिणाम रोल नंबर और नाम, दोनों के अनुसार देख पाएंगे। बोर्ड द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिस में यह कहा गया है कि बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम 29 जुलाई 2021 को दोपहर 12 बजे, नतीजे घोषित करेगा। छात्र अपना एमपी बोर्ड (शेष पेज 2 पर)

व्यापमं घोटाले में सीबीआई ने 73 आरोपियों के खिलाफ पेश की चार्जशीट

त्रिवेदी, नितिन, अजय और मिश्रा समेत 13 नए आरोपी बनाए

भोपाल (काप्र)।

पीएमटी-2012 में घोटाले में सीबीआई ने बुधवार को चार्जशीट पेश की है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिसौदिया की कोर्ट में 73 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

यह चार्जशीट पूरक चालान है। बुधवार को पेश चार्जशीट में 13 नए आरोपी बनाए गए हैं। इनमें मिडिल मैन (मध्यस्थ), चार पैरेंट्स, तीन मुन्ना भाई (छात्र की जगह बैठकर परीक्षा देने वाले) और 3 लाभार्थी शामिल हैं। चार्जशीट में व्यापमं (मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल) के तत्कालीन निदेशक पंकज त्रिवेदी, तत्कालीन वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिन्द्रा, तत्कालीन डिप्टी सिस्टम एनालिस्ट अजय कुमार सेन और तत्कालीन प्रोग्रामर सीके मिश्रा के नाम दर्ज हैं।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया, जांच निरीक्षक गुरजेंदर सिंह और कमलेश तिवारी ने की है। इसमें सामने आया, सैकड़ों छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इस परीक्षा घोटाले में 4 मेडिकल कॉलेजों में पीपुल्स, चिरायु, एलएन और इंडेक्स मेडिकल कॉलेजों की बड़ी भूमिका सामने आई है। इनके प्रबंधन पर आरोप है कि मेरिट में आने वाले छात्र-छात्राओं को सरकारी कोटे की सीटों पर दाखिला देते थे।

फिर उनसे सीटें स्वेच्छा से सरेंडर करवाकर कॉलेज की सीटों को मुंह मांगी कीमत पर बेचते थे। अनुमान के मुताबिक व्यापमं के पीएमटी के 2012 घोटाले में करोड़ों का लेनदेन हुआ था। हजारों छात्र-छात्राएं इससे प्रभावित हुए थे। सीबीआई ने जिन 13 लोगों को नए आरोपी बनाए हैं।

जयशंकर और ब्लिंकन ने विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को विभिन्न विषयों पर व्यापक वार्ता शुरू की। बातचीत के एजेंडे में अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे सुरक्षा परिदृश्य, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने, कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में सहयोग समेत अन्य विषय शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दोनों नेताओं के संग की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री (शेष पेज 2 पर)

बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

बेंगलुरु (एजेंसी)। बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यहां राज भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कर्नाटक में भाजपा के विधायक दल ने मुख्यमंत्री पद पर असमंजस को खत्म करते हुए मंगलवार शाम को 61 वर्षीय बोम्मई को अपना नया नेता चुना। बोम्मई ने कद्दावर नेता बी एस येदियुरप्पा का स्थान लिया है। उत्तर कर्नाटक से लिंगायत समुदाय के नेता बोम्मई को येदियुरप्पा का करीबी माना जाता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने में वरिष्ठ भाजपा नेता की पूरी (शेष पेज 2 पर)

इस साल पुरानी दरों पर ही होती रहेंगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नई जगह के लिए गाइडलाइन तय करेगी सरकार

भोपाल (काप्र)।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दर नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन की दरों पर ही 31 मार्च 2022 तक संपत्तियों की रजिस्ट्री होगी।

वहीं प्रदेश की 5 हजार नई जगहों पर दरें निर्धारित की जाएगी। माना जा रहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था। इसे 1 जुलाई से लागू किया जाना था, लेकिन सरकार ने पहले 15 जुलाई और फिर 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला किया था। अब सरकार ने इस वर्ष गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। इस वित्तीय वर्ष में मौजूदा गाइडलाइन से ही संपत्ति की रजिस्ट्री होगी। साथ ही 5 हजार ऐसे स्थान जहां दरें निर्धारित नहीं थीं, वहां दरें निर्धारित की जाएगी। मूल्यांकन बोर्ड ने जून माह में सरकार को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की सवा लाख लोकेशन पर 5 से 40 प्रतिशत तक दरें बढ़ाने का प्रस्ताव (शेष पेज 2 पर)

भोपाल में गृहमंत्री के नाम पर धमकी

निगमकर्मी को धमकाते हुए कहा- मैं नरोत्तम मिश्रा का पीए हूं, तुझे सस्पेंड कर दूंगा

भोपाल (काप्र)। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पीए बनकर धमकाने का मामला सामने आया है। नगर निगम के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक सुमनधर शर्मा के सोशल मीडिया पर दो ऑडियो सामने आए हैं। इसमें वह निगम के अन्य कर्मचारी को धमकाते हुए कह रहा है कि मैं गृहमंत्री का क्क हूं। तू मेरे घर आया कैसे? तुझे सस्पेंड कर दूंगा। दोबारा दिखा तो लात मारूंगा। ऑडियो में शर्मा ने निगम कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों के लिए भी अभद्र टिप्पणी की थी। ऑडियो सामने आने के बाद नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। गोवर्धन परियोजना शाखा में पदस्थ शर्मा के 4.11 और 5.23 मिनट के दो ऑडियो सामने आए हैं। इसमें वह कर्मचारी अमीन अवध मकोरिया से अभद्र व्यवहार और गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है। अमीन की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह कमिश्नर के आदेश पर ऐसे कर्मचारियों के मकानों की जांच करने गए थे, जो खुद के मकान होते हुए भी सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं। इसी बात पर गुस्साए शर्मा ने मकोरिया को धमकाया था। यह ऑडियो करीब एक महीने पुराने बताए जा रहे हैं। शर्मा ने मकोरिया से दो बार कुल 9.34 मिनट बात की। इस दौरान कई बार धमकियां दी थीं। उसने कहा कि मैं गृहमंत्री का पीए हूं। सीएम का पर्सनल सेक्रेटरी भी रहा हूं। मेरे घर जांच करने आया कैसे? क्या जांच करेगा। तू मेरे घर में आया कैसे। दोबारा दिखा तो तीन लात मारूंगा। कल ही तुझे सस्पेंड करा दूंगा। इस पर अमीन मकोरिया ने कहा कि मुझे कमिश्नर ने 48 मकानों की जांच करने के लिए भेजा था इसलिए आया। ऑडियो में मकोरिया ने कई बार शालीनता से बात करने को कहा, लेकिन शर्मा पूरे समय धमकाता रहा।

ओलंपिक में महिला खिलाड़ियों ने जगाई पदक की आस

मुक्केबाज पूजा रानी अंतिम 8 में पहुंची दीपिका-सिंधु का जोरदार प्रदर्शन

टोक्यो (एजेंसी)। ओलंपिक 2020 के छठे दिन भारत के लिए उम्मीद भरा रहा। बुधवार को भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा कुमारी 75 किग्रा वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इन दोनों से भारत को मेडल की उम्मीद हैं। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारतीयों को निराश नहीं किया। सिंधु ने हांगकांग की चीयूंग नगन यी को 21-9, 21-16 से मात देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम को अपने पूल ए मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पुरुष एकल तीरंदाजी में तरुणदीप राय को इज़राइल के इताय शैनी से शिकस्त झेलनी पड़ी।

स्पेशल खबर अनिल देशमुख मामले में...

सीबीआई ने महाराष्ट्र में 12 जगहों पर की छापेमारी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख की कथित रिश्वतखोरी के मामले की जांच में आगे बढ़ते हुए कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों की जांच तेज कर दी है।

सीबीआई ने मामले के संबंध में अपनी जांच के सिलसिले में एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के आवास सहित महाराष्ट्र में 12 स्थानों पर तलाशी ली है। सीबीआई के एक सूत्र ने बताया, कई लोगों की भूमिकाएं सामने आने के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र में 12 स्थानों पर तलाशी ली गई। सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने मुंबई और पुणे में एसीपी पाटिल के आवासीय परिसरों, जबकि मुंबई में डीसीपी भुजबल के आवासीय परिसर और अहमदनगर में तलाशी ली है। सूत्र ने कहा कि एसीपी और डीसीपी के अलावा सीबीआई ने नासिक, सांगली, ठाणे, सोलापुर और उस्मानाबाद जिलों में कई बिचौलियों के परिसरों पर भी छापेमारी की है। सीबीआई ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रारंभिक जांच करने के बाद 21 अप्रैल को देशमुख और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर निर्देश पारित किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुख ने शहर में बार और रेस्तरां से रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये की मांग की थी। 20 मार्च को, सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे आठ पन्नों के पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने अब निलंबित हो चुके एपीआई सचिन वाजे को मुंबई में 1,750 बार और रेस्तरां से 40 से 50 करोड़ रुपये सहित हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था। देशमुख पर संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप लगाया गया है।